साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 अंक 26 प्रति सोमवार इंदौर, 29 जनवरी से 04 फरवरी 2024 पृष्ठ 8 मूल्य 5/- रुपए

चीन की षड़यंत्रकारी कब्जा करो की नीति से विश्व भी परेशान

अमेरिका व नाटो भी चीन की हर जगह घुसपैठ से आशंकित

चीन ने नशेड़ी जनता को उत्पादक बना, सस्ता माल बेंच उत्पादकों को भी उपभोक्ता बना दिया

चीन के कम्युनिस्ट शासकों ने तानाशाही के दम पर भी जिस चीन को अफीमचियों और नशेड़ियों का देश कहा जाता था। मात्र

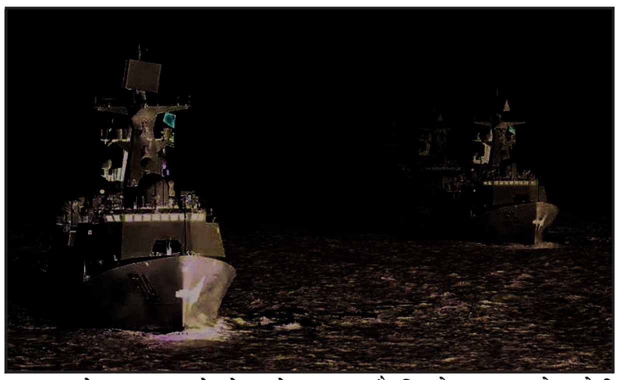

1980 के बाद अपने देश के उत्पादकों के साथ जहां वे कमजोर थे उन्होंने विदेशी कंपनियों व उनके उत्पादों को चीन में उत्पादन के लिए सस्ती बिजली सस्ता श्रम भूमि पानी उपलब्ध करवा कर करो से मुक्त सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की सस्ती विद्युत के तारों के उत्पादन से लेकर बल्ब विद्युत की झालरें वैद्युतकीय मोबाइल संचार की टावर लाइन टावर स्विच बोर्ड से लेकर मोबाईल फोन तक के उत्पादन में सैमसंग, एलजी, एप्पल टका पहले देश में उत्पादन करवाया बाद में सब कुछ सीख कर अपनी हुंडे से लेकर हुवावे ओप्पो वीवो श्यओमी पोको लेनेवो, से लेकर रक्षा संबंधी मिसाइलों के स्विच बोर्ड, राडार तक बनाकर जिनमें सभी में जासूसी करने वाले कैमरों से लेकर बंद मोबाइल स्क्रीन टीवी निगरानी रखने वाले कैमरों टक्कूचोरी सेफटकार पूरी दुनिया की जासूसी करने में लगा है जिसके कारण पूरे यूरोपी देश भी आतंकित व अशांकित हैं। में अनेकों कंपनियों ने सस्ता माल उत्पादित कर विश्व के बाजारों पर माल बेचने के बहाने कब्जा कर लिया। वायरलेस, कंम्प्युटर मदरबोर्ड कीबोर्ड अन्य सभी ऑडियो विजुअल सामग्री कैमरे आदि उपकरणों व अन्य सामग्री का उत्पादन कर विदेश की सरकारों को खरीद वहां पर सस्ता माल बेच वहां के उत्पादकों को 10 से 15 साल में समाप्त कर दिया। पूरे विश्व के बाजार में अमेरिका की जैसे उत्पादक देश को भी अपना माल बेंच, वहां की सरकारी अधिकारियों से दोस्ती के संबंध बना घूस खिला, धीरे-धीरे उसके करएम वहां कीसत्ता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जैसा ऑस्ट्रेलिया वह अन्य देशों में हुआ। पूरा अमेरिका उसकी नाटोवह यूरोप की अन्य बड़ी सभी प्रकार के उत्पादक कंपनियां चीन के सस्ते माल के मुकाबले बाजार में नहीं टिक पा रही है। दूसरी तरफ वह लगातार अपनी जल थल नभ में सेना को मजबूत करनेमें लगा रहकरउसने अधिकांश राइफल पिस्टल से लेकर भारी लड़ाकू विमान जहाज से लेकर पनडुब्बियां अंतरिक्ष के उपग्रह तक अपने देश में बनाकर वहरूस और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर का हथियार उत्पादक देश बन चुका है जिससे पूरे रूस, अमेरिका ब्रिटेन इजरायल की शहनाई भीउसके जल थल और नभ में बढ़ते प्रभाव से आतंकित हैं।

रक्षा सुरक्षा समुदाय के अनुसार चीन सबसे बड़ा खतरा

किसी भी दरार के माध्यम से रहस्यों को उजागर करने पर आमादा राष्ट्र-राज्य के खिलाफ बचाव के लिए सरकारों और निगमों को एक साथ काम करने के तरीके खोजने की आवश्यकता होगी।

(शेष पेज 5 पर)

मप्र में पेट्रोल-डीजल सबसे ज्यादा महंगा

रू. 109 से 120 की वसूली

रु. 78 केंद्र राज्य करों के साथ भारी टोल टैक्स भी

4-5 गुना कीमत चुकाने के बाद में भी मिलावट व चोरी से जनता ठगी जा रही

पूरे देश व दुनिया में सबसे ज्यादा आमजन की कमाई की तुलना में सरकारी नियंत्रण और कंपनियों के बाद में भी पेट्रोल-डीजल गैस में लूट का तांडव मध्य प्रदेश में चल रहा है। केंद्र के 27% उत्पाद कर के बाद में भी 2% सड़क, कृषि और आधार संरचना, शिक्षा, चिकित्सा, मध्यान्ह भोजन व अन्य के नाम 7 से ज्यादा प्रकार के उपकर लिए जाते हैं। प्रदेश की सरकार लगभग 36% वेट लगती है जो कि दूसरे प्रदेशों में 27, 25 और 22 तक है। जिससे मध्य प्रदेश में पेट्रोल 109 रु. प्रति लीटर इंदौर में, जबकि वहीं पेट्रोल अलीराजपुर झाबुआ में रुपए 115 से लेकर हाई स्पीड 122 तक पड़ता है। इतना टैक्स लूटने के बाद में भी मध्य प्रदेश सड़क डकैती विकास निगम की सड़कों पर कारों पर एक से रु. 2 किमी और राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों पर रु दो से लेकर रु. 10 तक का भारी भरकम टोल टैक्स प्रति किलोमीटर वसूला जाता है। केंद्र सरकार का भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लंबी चौड़ी फांकता जरूर है। परंतु भ्रष्टाचार में वह रिश्ते में इन सब का बाप लगता है। क्योंकि जो सड़क रू 80 लाख 5 मी चौड़ी किलोमीटर टोल से लेकर रु. 25 प्रति किलोमीटर का टोल बसूला जा रहा है जो मुंबई के समुद्र में बने ब्रिज पर 21 किलोमीटर लंबे पुल पर एक बार का रु. 550 कार का लगता है।

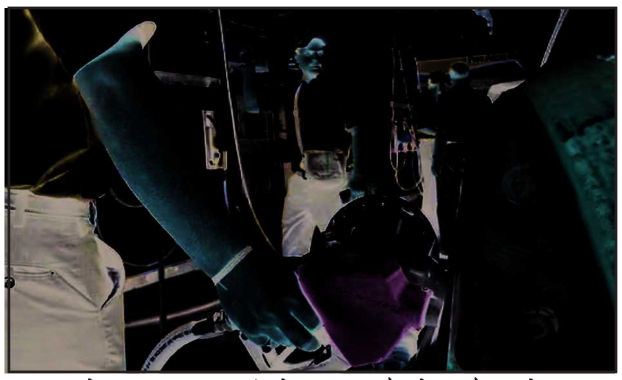

प्रति किलोमीटर सड़क राज्यों के लोक निर्माण विभाग दो करोड रुपए किमी में बनाते हैं। वही सड़के और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कें 10 गुना महंगी बनाने के साथ सारा पैसा बैंक से लिया जाता है पर वह पैसा सरकारी खर्चे में दिखाया जाता है। कि हमने इतना पैसा सड़क बनाने पर खर्च किया पर यथार्थ यह है कि वे सारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कें बैंक कर्ज से मोदी के खास मित्र अडानी के माध्यम से नितिन गडकरी की साझेदारी में बनवा रु. 5 प्रति

इंदौर से उज्जैन जाने पर जहां 50 किलोमीटर का 35 रुपए वही इंदौर से धार जाने पर 50 किमी का रू 325 लगता है। कहानी शुरू होती है जब सीपीडब्ल्यूडी सारे कार्यों की दरें निर्धारित करता है और वही एस. ओ. आर पूरे देश में लागू किया जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की डीपीआर 5 से 20 गुना ज्यादा तक कैसे और क्यों बनाई जाती है। इस पर भारत का महालेखाकार जो केवल कागजी स्वान है।

(शेष पेज 2 पर)

भाजपा नेता की मौत पर गरमाई सियासत

जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर लगाए गंभीर आरोप

उज्जैन में मूर्ति विवाद पर बवाल और फिर बीजेपी नेता की हत्या के मामले पर सियासत गरमाई हुई है. सीएम मोहन यादव के गृह जिले में लगातार सामने आ रही इन घटनाओं पर कांग्रेस उन्हें घेर रही है. पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन यादव ने अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

नए सीएम ने तोड़ा अपराधों का रिकॉर्ड- पटवारी

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि एक दिन पहले उज्जैन के माकड़ोन में सरदार पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ. उससे पहले उज्जैन में कई आपराधिक घटनाएं हुईं. प्रदेश में अपराध का बोलबाला है. शिवराज जी ने भी करप्शन का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया. हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने करप्शन के साथ अपराधों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

अपराधों को कंट्रोल करे सरकार

जीतू पटवारी ने हमला करते हुए कहा कि मोहन यादव खुद मुख्यमंत्री भी हैं और गृहमंत्री भी

हैं. वे धार्मिक बातें करते हैं, लेकिन सब धर्मों का मूल है सामाजिक भलाई और मानवता की रक्षा करना. मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के हालात दयनीय हैं, अपराध के मामले में. मध्य प्रदेश की जनता संकट में है. बलात्कार हो, हत्याएं हों, सामाजिक झड़प हों और महापुरुषों को मूर्तियों पर हमला, हर तरह का अपराध यहां है. जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार अपराधों को कंट्रोल करे.

सीएम के एक्शन का रिएक्शन- जीतू पटवारी

जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव के अधिकारियों को ताबड़तोड़ सस्पेंड करने के एक्शन पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि एक के बाद एक अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के किए गए एक्शन का रिएक्शन हुआ है. इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री के किसी एक्शन से अफसरशाही डरती नहीं है. जीतू पटवारी ने कहा कि आप मुंह चलाते हो रोज, कलम कब चलाओगे.

शिवराज-मोहन के बीच राजनीतिक द्वंद

जीतू पटवारी ने मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश गान के सम्मान के खड़े होने के रिवाज को बदलने पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले को बदलने को गलत ठहराया. पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि आपके आपसी राजनीतिक द्वंद से मध्य प्रदेश के हितों का कुठाराघात क्यों हो रहा है.

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

मूढ़ डकैतो ने लूट के चक्कर में अधिकांश मौके गंवाए। बेरोजगारी भुखमरी में झोंक दिया देश को।।

आपराधिक मानसिकता के मूढ़ मोदी अमित शाह ने देश के हिंदुओं की धर्मभीरुता का ऐतिहासिक घोर शोषण करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक मुखौटा भारतीय जनता पार्टी में प्रारंभ में इसमें बुद्धिजीवी नेतागण थे परंतु सैंध लगा अपराधियों ने अपने अपराधों से बचने व डर बनाने के लिए इसमें घुस अपराधियों ने छल, बल, दल से वरिष्ठ नेताओं का विश्वास जीत पैठ बना बाद में उनकी कमजोरियों को आधार बना ब्लैकमेल कर पूरी पार्टी पर ही कब्जा कर सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। जिनका एकमात्र मूल उद्देश्य था हर तरह से देश की संपत्तियों, संस्थाओं को बैच गिरवी रख मोटा पैसा इकट्ठा करना चाहे फिर चीन जैसे शत्रुओं से ही गुप्त रूप से हाथ मिला देश को नीलाम ही क्यों न करना पड़े। वे चूके नहीं। जबकि यदि लूट की मानसिकता नहीं होती तो वह ऐतिहासिक रूप से घोर नीच चीन जैसे पड़ोसी देश को आसानी से पानी पिला सकते थे और अभी भी कर सकते हैं। परंतु उल्टे ही जब मोदी 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए चीन गया तो उसने वहां की सरकार व कंपनियों से मोटा पैसा खाकर सबसे ज्यादा बर्बादी गुजरात की ही की। जिस गुजरात का हीरे रत्नों से लेकर खिलौने फार्मा मशीन टाइल्स कपड़े साड़ियां रसायन नमक आदि के उत्पादन और व्यवसाय में पूरे देश भर में सिक्का चलता था वहां पर भी उसने चीनी कंपनियों को घुसेड व सुविधायें देकर गुजरात के उद्योगों को उनके ही प्रदेश में उनका प्रतिद्वंदी बना चौपट कर दिया। उसने यही खेल देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के स्तर पर भी खेला। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अपने मित्रों के फायदे के लिए मोटा कमीशन खाकर देश के राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को रिजर्व बैंक से लेकर नीचे के सरकारी छोटे-छोटे बैंकों तक के लगभग विभिन्न प्रकार के 40 लाख करोड रुपए से ज्यादा के कर्जों को माफ किया। जिसमें 15 लाख करोड रुपए ही स्वीकार किए जाते हैं। बैंकों में जनता का धन जमा होता है। उस जनधन को लूटने के साथ जनता का बैंकों पर विश्वास हटाने जनता की जमाओं को भी 5 लाख तक ही डूबने पर पुनः मिलने योग्य माना। ऐसे ही लाखो लूट के किस्सों का इतिहास लिखा गया। जनता का विश्वास खोया पर मिडिया को लगातार जनधन लुटा विज्ञापन बांट छल बल दल से ड्रा धमका काबू में रखने के कारण वह सच सामने नहीं आने दिया जा रहा। जबकि मोदी व उसका गिरोह अपनी लूट डकैती को छुपानै पाखंड करने की अपेक्षा, तरीके से पूंजीपत्तियों को नियंत्रित करता। चुनाव में लिये धन की भरपाई के लिये अपने पूंजीपति मित्रों व आमजन के लिए नए उद्योग लगाने, चीन दोस्ती के बहाने उन देशों मैं पहले सस्ते स्तर हीन अविश्वसनीय माल की बिक्री फिर उत्पादन, फिर सरकारों को धन देकर कब्जा जमाने के षड्यंत्रों से पूरे विश्व में बढ़ते अविश्वास का लाभ उठाने, नए उद्योग में कर छूट, सस्ती बिजली पानी सड़कें आदि की सुविधायें देकर अपने पूंजीपति मित्रों को विश्व स्तर की कंपनियों के साथ जो चीन की हड़पो नीति से परेशान हैं। संयुक्त उपक्रम में उत्पादन करवा करोड़ों लोगों को रोजगार दे एक तरफ जनता को खुश करता तो दूसरी तरफ पूंजीपति मित्रों का कर्ज उतार पूरे विश्व के बाजारों में अच्छे और सस्ते माल का निर्यात कर धाक जमा विश्व गुरु बन सकता था। पर वह तो उल्टे ही अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों व चीन की गोदी में बैठ मोटा कमीशन हड़प कर उसने देश व देश की 140 करोड़ कीड़े मकोड़े जनता व देश की प्राकृतिक व मानव निर्मित संपत्तियों को जाहिल ने सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी के नाम देश में बेरोजगारी भुखमरी का तांडव करवाअपने बाप की जागीर मान, हर तरह से लूटने, लुटवाने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और जनता को भ्रमित करने के लिए पहले हिंदू मुस्लिम फिर अगड़ी पिछड़ी फिर आदिवासी बनाम पिछड़ा बनाम अनुसूचित जातियों के आपसी संघर्षों को बढ़ावा देना, मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता को उलझा कर रखने का खेल खेलकर भ्रष्टता, धृष्टता का विश्वगुरू बन गया।

मप्र में पेट्रोल-डीजल सबसे ज्यादा महंगा, रू. 109 से 120 की वसूली

पेज 1 का शेष

जिसके विभाग में इंजीनियर नहीं होते जो डीपीआर की भाषा को बारीकी से समझ कर उसमें किए गए प्राथमिक स्तर के भारी भ्रष्टाचार को पकड़ सकें। जब पांच से 10 गुना ज्यादा की डीपीआर बनवाई जाएगी। बैंक उसका 75% लोन दे देगा।

हाल ही में इस पर सीएजी ने इन तथ्यों पर उंगली उठाकर नितिन गडकरी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। स्वाभाविक है. 20-25% में काम हो जाएगा। बाकी 75% पैसे में से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों को स्वीकृत करने वाले केंद्रीय शहरीय व ग्रामीण विकास, वन एवं पर्यावरण, वित्त, भूतल मंत्रालयों मैं बैठे घोर भ्रष्ट मंत्री प्रधान सचिव अधिकारी प्रति किमी एक करोड रु. स्वीकृति देने में ही खा जाते हैं। जब सारी देशभर की राष्ट्रीय व राज्यों की राजमार्ग की सड़कें टोल टैक्स के अंतर्गत ही बनवाए जा रही है तो सरकार सही क्यों लेती है और पेट्रोल डीजल गैस में 78% तक का टैक्स लेने का क्या औचित्य है?

दूसरी तरफ वर्तमान में जब से यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हुआ है रूस भारत को 60% तक क्रूड की आपूर्ति कर रहा है।जो बाजार की कीमतों से 25% तक कम होने के साथ उसका भुगतान भी रूबल का रुपए में किया जा रहा है अर्थात $50 पर बैरल का जिसमें 159 लीटर होते हैं 20-25 रु लीटर के पेट्रोल में गन्ने से शक्कर बनाने में निकलने वाले एथेनॉल का 20% पेट्रोल में मिलाया जा रहा है. अर्थात वह पेट्रोल लगभग 15-18 रु होने के बाद में भी जनता को 109 रु लीटर उसमें भी क्योंकि एथेनॉल में पानी निकलता है।

शातिर पेट्रोल पंप वाले उसमें सीधी ही पानी की मिलावट कर देते हैं। और पेट्रोल भी 1 लीटर की स्थान प्रति माह 700 से 900 मिली लीटर ही देते हैं। जो जनता को जाकर 130 से 150 रुपए लीटर तक पड़ता है और गाड़ियां खराब होती है गाड़ियों की टंकी में 10 लीटर की टंकी में कई बार दो-दो तीन लीटर पानी तक निकलता है इसके लिए बाकायदा पेट्रोल पंप वालों ने बोर्ड लगा दिया है और सरकार ने गाड़ियों की बनावट भी इस पानी की मिलावट के लिए बदलवा दी है।

अर्थात गुजराती डकैत ने भी जनता के साथ लूट में कोई कसर नहीं छोड़ी है इसके साथ ही पेट्रोल पंप वालों से नापतोल के निरीक्षकों का महीना बंधा होता है वही हाल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के निरीक्षकों का भी वहां से महीना बंधा होता है जिनकी जिम्मेदारी होती है की जनता को शुद्ध और पर्याप्त पेट्रोल निश्चित कीमत पर मिल सके। कुछ राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट से इसके बारे में नीचे लगाई गई है। वह भी सरकारी दी गई आंकड़ों के हिसाब से।

मध्य प्रदेश में की इतनी अधिक पेट्रोल डीजल गैस में लूट होने के बाद में भी मध्य प्रदेश सरकार का परिवहन विभाग केंद्र सरकार के नियमों को नहीं मानता। क्योंकि वह इससे ऊपर है और यहां के हरामखोर सारे के सारे परिवहन मंत्री आयुक्त उपायुक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिलों के परिवहन अधिकारी निरीक्षक जो अपने भ्रष्टाचार लूट और जाल साजियों के लिए कुख्यात हैं। चालक अनुकृति के नाम पर केंद्रीय शुल्क रु. 200 की अपेक्षा रुपए ढाई हजार नवीनीकरण अंतरण नाम पता परिवर्तन की रु.1000 की जगह रु. 10500 तक का शुल्क वसूलते हैं इसके साथ ही वह अपने इस भ्रष्टाचार को छुपाने अपनी ही परिवहन विभाग की साइट पर शुल्कों के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। हर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मैं निजी बसों के परमिट के नाम पर ही प्रतिदिन करोड़ों का लेनदेन हो जाता है। क्योंकि हर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 2 से 5000 बसें पंजीकृत हैं। जो बस रूट पर परमिट का खेल खेलती है। जिसमें कलेक्टर कमिश्नर का भी अपना हिस्सा होता है।

सड़क उपकर राजस्व पार करने के लिए कुछ केंद्रीय योजनाओं पर खर्च

केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाए गए सड़क और बुनियादी ढांचे उपकर और कर योग्य आय पर उपकर से रु. 1.92 लाख करोड एकत्र करने के लिए तैयार है

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023 में कुछ विकास योजनाओं पर केंद्र सरकार का खर्च इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए कर योग्य आय और पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर से एकत्र राजस्व की मात्रा से अधिक हो जाएगा।

सरकार पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाए गए सड़क और बुनियादी ढांचे उपकर के साथ-साथ कर योग्य आय पर उपकर से रु. 1.92 लाख करोड एकत्र करने के लिए तैयार है। हालाँकि, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इन दो प्रकार के उपकरों द्वारा वित्तपोषित विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च FY23 में रु. 3.18 लाख करोड होने का अनुमान है। यह अंतर भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा।

केंद्र द्वारा लगाया गया उपकर, विशेष रूप से ऑटो ईंधन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, हाल के महीनों में बहस का विषय बन गया है और कई राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं कि उपकर की आय उनके साथ साझा किए जाने वाले करों के पूल में नहीं जाती है। केंद्र ने बताया है कि उसने 2014 के बाद से लगभग रु. 91 लाख करोड विकास व्यय किया है। आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया जाता है।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पेयजल और स्वच्छता, सड़क और राजमार्ग और ग्रामीण विकास ऐसे क्षेत्र हैं जहां वित्त वर्ष 2012 के संशोधित अनुमान की तुलना में वित्त वर्ष 2013 में अधिक मात्रा में उपकर उपयोग का अनुमान है। पेयजल और स्वच्छता के लिए, वित्त वर्ष 2013 में ?67,190 करोड़ से अधिक खर्च किया जाना है, जो वित्त वर्ष 2012 में रु. 51,000 करोड़ से अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क कार्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव में निवेश के लिए उपकर का उपयोग वित्त वर्ष 2023 में रु. 1.29 लाख करोड से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में रु. 89,140 करोड़ से अधिक है।

केंद्र को इस वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से रु. 53,846 करोड़ एकत्र होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में एकत्रित रु. 47,307 करोड़ से अधिक है। हालाँकि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट जैसी परियोजनाओं के तहत चालू वित्त वर्ष में उपकर उपयोग की सीमा रु. 86,100 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में रु. 81,499 करोड़ थी।

नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, 'न केवल इन उपकरों से विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास गतिविधियों को वित्त पोषित किया गया है, बल्कि सरकार ने उपकरों से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं को वास्तविक संग्रह से अधिक प्रदान किया है।'

देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण भाजपा सरकार की आलोचना हो रही है क्योंकि कई राज्यों में पेट्रोल अब 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर बेचा जा रहा है। मप्र में दुनिया का सबसे महंगा रु116 हाई स्पीड पेट्रोल बल्कि रहा है।

केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32.90 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क/उपकर लगाती है, जिसमें रुपये का मूल उत्पाद शुल्क भी शामिल है। 1.40, सड़क और बुनियादी ढांचा विकास उपकर 18 रुपये, कृषि और बुनियादी ढांचा विकास उपकर रुपये। 2.50 और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 11 रु. सरकार ने कहा कि पेट्रोल, डीजल से प्राप्त राजस्व का उपयोग केंद्र की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसी योजनाओं द्वारा महामारी के दौरान गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए, जिसके तहत अप्रैल, 2020 से नवंबर 2020 और मई-जून 2021 के दौरान 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान किया गया, सीओवीआईडी -19 के लिए मुफ्त टीकाकरण किया गया। वगैरह।

यहां उल्लेख करने योग्य बात यह है कि पिछले 7 वर्षों में, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किमी (अप्रैल 2014 तक) से 50% बढ़कर 1,37,625 किमी (20 मार्च 2021 तक) हो गई है। भारत में प्रति दिन राजमार्ग निर्माण 2014-15 में 12 किमी/दिन से लगभग 3 गुना बढ़कर 2020-21 में 33.7 किमी/दिन हो गया है। सरकार ने आज लोकसभा में उठाए गए सवालों के जवाब में कहा कि उपकर का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है और रोजगार भी पैदा करता है।

देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण भाजपा सरकार की आलोचना हो रही है क्योंकि कई राज्यों में पेट्रोल अब 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर बेचा जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है।

सरकार ने आज कहा कि केंद्रीय शुल्कों के अलावा, राज्य पेट्रोल और डीजल के आधार मूल्य और केंद्रीय करों की कुल राशि पर भी वैट वसूलते हैं, जो रुपये से भिन्न होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4.83 रु. महाराष्ट्र में 29.55 रु. राजस्थान में 29.88 रुपये, जिससे दोनों ईंधन की खुदरा कीमतों में उछाल आया। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिसका असर खुदरा कीमतों पर पड़ रहा है।

पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों का महंगाई पर असर पर सरकार ने कहा कि WPI सूचकांक में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का भार क्रमशः 1.60%, 3.10% और 0.64% है।

इंदौर नगर निगम : हर कदम मनचाही डकैती

18 वर्ष बाद भी आरटीआई 2005 का पालनार्थ जानकारी नहीं साइट पर

महापौर भार्गव साइट पर हर विभाग की 25 बिंदुओं की जानकारी क्यों नहीं अपलोड करवाते

देश के महानगरों से पंचायतों तक स्वशासी, क्षेत्रीय, शासकीय संस्थान मंत्रालय से लेकर नीचे तक हर कदम कदम पर भारी भ्रष्टाचार लूट डकैती जालसाजियों में आकंठ लिप्त हैं। इसी भ्रष्टाचार को रोकने संविधान के अनुसार जनता से वसूले के पैसे का पाई पाई का हिसाब देने देश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लगाया गया था जिसमें सरकार वह सभी सरकारी संस्थाओं को 100 में पहले 17 बिंदुओं की और बाद में उसमें आठ बिंदु और जोड़े गए इस प्रकार 25 बिंदुओं की जानकारी अपने विभाग की पारदर्शीता प्रदर्शित करने के लिए अपलोड कर देनी चाहिए थी। जो सूचना का अधिकार अधिनियम लगे 18 साल गुजर जाने के बाद में भी आतंक भ्रष्टाचार में डूबे होने के कारण लोड नहीं की जा रही वही हाल इंदौर नगर निगम का है जनता से लूटने के लिए विभिन्न प्रकार के बहाने कर, मनचाही लूट, मनचाहे शुल्क, यहां तक की एक ही प्रदेश की राजधानी में गृह निर्माण के अलग-अलग दरें जिसे भास्कर ने छापा है दी गई है।

उपरोक्त विवरण से लगता है कि जब चाहे जैसे चाहो आमजन के ऊपर उसकी परेशानियों से दूर उसको लूटना और परेशान कैसे करना है कब षड्यंत्र हर स्तर पर नगर निगम में होता है यहां तक की स्मार्ट सिटी के नाम परमकान बनाने की नक्शा की स्वीकृति का शुल्क हजार रुपएप्रति वर्ग फुट कर दिया अर्थात 1000 वर्ग फीट के मकान में 10 लाख रु स्वीकृति का शुल्क लगेगा। चाहे मकान बनाने वाले के पास प्लॉट भी उसने कर्ज में लिया हो उससे कोई मतलब नहीं। इन डकैतों को लूटना है और लूटना है। यह तो सरकारी शुल्क हुआ फिर नगर निगम में किसी भी टेबल पर कोई भी काम

मुफ्त में नहीं होता चारों तरफ डकैतों का गिरोह आयुक्त उपायुक्त सहायक आयुक्त इंजीनियरों से लेकर सफाई कर्मियों तक अधिकांश वेतन से 10 से 100 गुना तक कमाते हैं और इस सच की पुष्टि करने के लिए उन हरामखोरों के केवल 6 महीने के कॉल डिटेल निकलवा लो शायद ही कोई चरण पखारने लायक ईमानदार मिलेगा।

फिर जल शादी से ही सही वर्तमान में तो जनता को इवीएम के फर्जीवाड़े से चुने महापौर पूर्व में उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता थे। अर्थात कानून के ज्ञाता तो है। तो उन कानूनों का पालन पूरी तरीके से साल भर गुजर जाने के बाद क्यों नहीं किया जा रहा। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के 25 बिंदुओं की जानकारी जिसमें हर प्रकार की खरीदी बिक्री, भुगतान प्राप्तियां सभी प्रकार के निगम के शुल्क सभी संपत्तियां बाजारों उनकी निगम की दुकानों के किराए भाड़े की प्राप्तियां निर्माण कार्य, कितने भावनाओं को कहां पर निर्माण की स्वीकृति दी गई वहां पर उसका नक्शा लागत कार्य पूर्णता की तिथि आदि का विवरण भी चाहे वह भवन, नाली पुल सड़कें सरकारी हो या निजी का विवरण भी लगाया जाना चाहिए। ताकि लोग वहां पर की जा रही जालसाजियों को समझ सकें। कर्मचारियों अधिकारियों की संपत्तियां की घोषणा के साथ उनको आवंटित कार्य शिक्षा कहां से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं आदि की सारी जानकारी भी साइट पर लोड होनी चाहिए? जिसे महापौर को अभी तक करवा लेना चाहिए था शायद उनको भी कानून से नहीं कमाई से मतलब है। इसी श्रृंखला में सिरपुर तालाब की जलकुंभी 35 दिन में 10000 ट्रक निकलने का कारनामा भी विश्व स्तरीय है।

अब आप सोचिए इन 10000 डंपर में आने जाने में 50 किमी डीजल के पैसे ही रू 100प्रति ली 5 लाख किमी के 5 किमी प्र ली औसत से 1 लाख लीटर डीजल एक करोड रुपए का हो गया। अब इसमें ही 80% पैसा हजम। ऐसे जनता के पैसे सेभरे तालाब को खाली किया जाता है।

इंदौर के नक्शे...प्लॉट पर निर्माण के लिए भी निगम ले रहा डिमोलिशन चार्ज, भोपाल से डेढ़ गुना फीस

इंदौर नगर में भवन निर्माण के नक्शे की मंजूरी के लिए मनमानी फीस वसूली जा रही है। यहां तक कि खुले प्लॉट पर मकान बनाने की मंजूरी देने के लिए डिमोलिशन यानी तोड़फोड़ का शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि प्लॉट में निर्माण के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अलग फीस ली जा रही है और उसका वादा करने के चार्जेस अलग लिए जा रहे हैं, जबकि भोपाल में गिनती की चार मदों में शुल्क वसूल कर नक्शा पास कर दिया जा रहा है। दोनों शहरों की नक्शा मंजूर करने की फीस में डेढ़ गुना से भी ज्यादा का अंतर है। नगरीय प्रशासन मंत्रालय पूरे प्रदेश में 1100 वर्गफीट तक के भवन के नक्शे 24 घंटे में मंजूर करने की सुविधा भले शुरू कर दी है, लेकिन इंदौर में इसकी फीस लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है।

पिछले साल इन शुल्कों में नगर निगम द्वारा बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद छोटे प्लॉट के नक्शे स्वीकृत करने के लिए भी 25-30 हजार रुपए का खर्च बढ़ गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि पहले रेसिडेंशियल शुल्क सिर्फ तीन मंजिला व उससे अधिक के भवनों पर लिया जाता था, लेकिन अब वह दो मंजिला मकानों से भी लिया जा रहा है। इसके अलावा पहले जो शुल्क प्लॉट साइज के हिसाब से लिए जाते थे, उन्हें अब स्लैब एरिया के हिसाब से वसूल किया जा रहा है। इससे भी शुल्क काफी बढ़ गया है। इसके विपरीत भोपाल में अभी भी सामान्य दरों से शुल्क वसूला जा रहा है। वहां डिमोलिशन, रेसिडेंशियल, प्लांटेशन जैसे अतिरिक्त मद के नाम पर फीस वसूली नहीं हो रही है।

देखिए... कितना फर्क है इंदौर और भोपाल के नक्शा मंजूरी की फीस में, दोनों के मद ही अलग

इंदौर — कुल खर्च 66035

ड्रेनेज कनेक्शन के लिए खुदाई का शुल्क	1200
पाटडी फीस	1830
डेवलपमेंट फीस	0.00
सॉलिड वेस्ट	1001
नल कनेक्शन खुदाई शुल्क	1200
रेसिडेंशियल फीस	16900
अनुमति शुल्क	2000
रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क	300
डिमोलिशन चार्ज	8450
पौधारोपण शुल्क	500
आवेदन शुल्क	14
नर्मदा कैपिटल रिनुअल	10010
टॉयलेट फीस	600

• बाहरी विकास- 1 • प्लॉट डिविजन फीस- 1 • पार्किंग कवर्ड कमिटमेंट चार्ज- 1 • प्रीमियम एफएसआई पर 1 • फॉर्म शुल्क- 1 • वाटर हार्वेस्टिंग कमिटमेंट चार्ज- 1 • कमर्शियल फीस- 1

कुल - 44163 • इसके अतिरिक्त 21872 रु कर्मकार शुल्क अतिरिक्त कुल खर्च - 66,035

भोपाल — कुल खर्च 41550

व्यावसायिक कर	200 रु. से 1000 रु. तक प्लॉट साइज के अनुसार
डेवलपमेंट चार्ज	8 रु. वर्गफीट
कोलार हाउसिंग बोर्ड व बीडीए की कॉलोनी में	28 रु. वर्गफीट
अवैध कॉलोनियों में	300 से 400 रुपए वर्गफीट
कर्मकार मंडल शुल्क	12 रु. वर्गफीट
सर्विस चार्ज	50 पैसे वर्गफीट
रेन वाटर हार्वेस्टिंग	7000 से 15000 तक

(1500 वर्गफीट व उससे बड़े प्लॉट पर)

...यानी 1000 वर्गफीट के भूखंड पर यदि अधिकतम दर भी लगाई जाए तो

व्यावसायिक कर	1000
डेवलपमेंट चार्ज	28000
कर्मकार शुल्क	12000
सर्विस चार्ज	500
फॉर्म का शुल्क	50
कुल	41,550

* दोनों नगर निगम में हाल ही में स्वीकृत हजार वर्गफीट के नक्शों के अनुसार।

नियमों का उल्लंघन... ट्रस्ट से भी मांगी लाखों रुपए की कमर्शियल फीसः मप्र भूमि अधिनियम के तहत पारमार्थिक ट्रस्ट को विभिन्न प्रकार की छूट प्राप्त है, लेकिन हाल ही में नगर निगम ने एक ट्रस्ट के निर्माण के लिए भी लाखों रुपए की कमर्शियल फीस मांगी। यहां तक कि लाखों रुपए डिमोलिशन चार्ज के भी मांगे गए, जबकि वहां भी खुले प्लॉट पर निर्माण किया जाना था।

अब तक बदलाव नहीं... स्मार्ट सिटी के नक्शों का भी अब तक निराकरण नहींः स्मार्ट सिटी क्षेत्र में कई आश्वासन के बावजूद लाखों की फीस ली जा रही है। छोटे प्लॉट पर निर्माण लागत के बराबर शुल्क देना पड़ रहा है। हाल ही में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 500 वर्गफीट तक नक्शे सामान्य दरों पर मंजूर करने की घोषणा जरूर की थी।

सिरपुर तालाब से डेढ़ महीने में निकाली 10 हजार डंपर जलकुंभी

2 फरवरी को यही होगा रामसर कन्वेंशन, सफाई और अन्य काम पर सवा करोड़ खर्च

2 फरवरी को इंटरनेशनल वेट लैंड डे पर सिरपुर तालाब पर रामसर कन्वेंशंस होगा। इतने बड़े आयोजन के लिए तालाब क्षेत्र की सफाई नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती थी। इसलिए करीब 2 महीने पहले काम शुरू किया था, जो अब पूरा होता नजर आ रहा है। इस दौरान निगम ने डेढ़ महीने में तालाब से 10000 से ज्यादा डंपर जलकुंभी निकली जो ट्रैकिंग ग्राउंड पहुंचाई है।

अब तक 10000 डंपर जलकुंभी हटाई गई इसके लिए निगम के वर्कशॉप में बनी छोटी हार्वेस्टर मशीनों के अलावा दो मशीनों किराए पर ली एक मशीन रतलाम निगम से बुलवाई गई। इसके अलावा आठ पोकलेन मशीन और 9 नाव लगातार तालाब में चलती रही। हर दिन सौ मजदूरों ने मेहनत की तब जाकर जलकुंभी पूरी तरह से साफ की जा सकी है। रामसर कन्वेंशन के लिए अन्य छोटे कामों को भी तकरीबन पूरा कर लिया है जिन पर करीब 1.10 करोड़ खर्च हुए हैं निगम के जल यंत्रालय विभाग का कहना है कि इस महीने सिरपुर तालाब को कन्वेंशन के लिए पूरी तरह तैयार कर इवेंट कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा जो 2 फरवरी के आयोजन के लिए इंतजाम करेगी।

सीवरेज के पानी के कारण पनप रही है

छोटे सिरपुर तालाब में जलकुंभी पनपना का कारण यही सीवरेज का पानी मिलाना बताया जा रहा था इसका स्थाई इंतजाम भी नगर निगम कर रहा है। दरअसल यहां से गुजरने वाली 400 एमएम चौड़ाई की पाइप सीवरेज ले जाने के लिए छोटी है। जिससे आने वाला सीवरेज का पानी बैकफ्लो में तालाब में जा रहा है। हालांकि फिलहाल इस क्षेत्र में 10 एमएलडी सीवरेज आता है, जिसमें मुख्यतः अहिरखेड़ी में पीएमएवाय (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत बनी मल्टी और आसपास की कॉलोनी से आ रहा है। हालांकि निगम अब यहां 20 एमएलडी का एसपी बन रहा है जो पूरे क्षेत्र के अगले 20 साल की जरूरत है हिसाब से पूरे पर्याप्त होगा। इससे उपचार किया गया पानी ओवरहेड टैंक बनाकर 10 किलोमीटर पाइप लाइन के जरिए सिंचाई और गार्डनिंग के लिए दिया जाएगा। इस एसपी के में तक पूरे होने की उम्मीद है। इसके बाद तालाब में गंदा पानी मिलना बंद होगा और यह साफ रह सकेगा निगम के कार्यपालन यंत्री जल यंत्रालय और ड्रेनेज सुनील गुप्ता ने बताया कि तालाब में अब दोबारा जलकुंभी पर अपने नहीं दी जाएगी।

दुनियाभर के सेलेब्स फॉलो करते हैं [illegible] डाइट

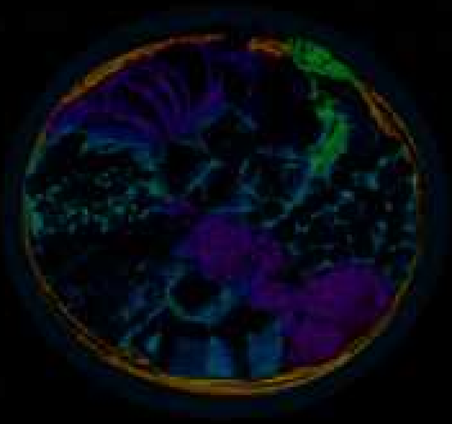

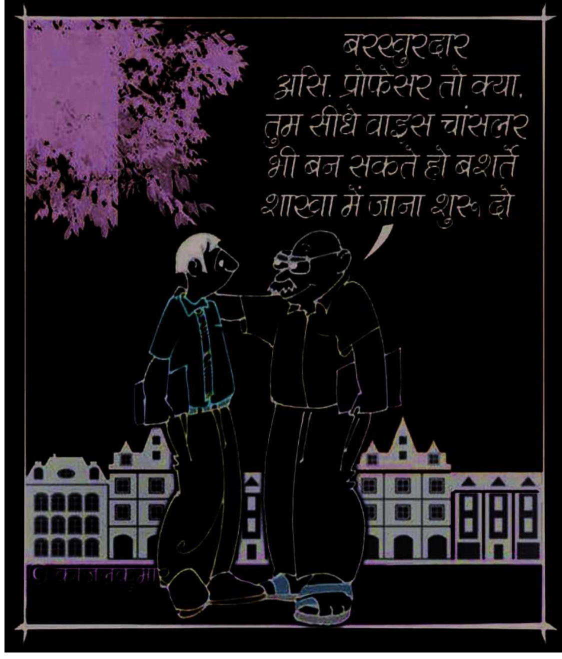

अच्छी सेहत के लिए जरूरी हैं ये टिप्स

- खाना नीचे बैठकर और हाथों से खाना चाहिए. खाने को अच्छी तरह चबाएं.
- खाना खाते हुए फोन, टीवी, लैपटॉप आदि सभी गैजेट से दूर रहें.
- रोजाना डाइट में मुट्ठीभर नट्स जरूर खाएं. सुबह के समय अखरोट या बादाम और दोपहर के समय मूंगफली या काजू का सेवन सही रहता है.
- मौसमी हरी सब्जियों का सेवन करें.
- रागी, ज्वार जैसे मोटे अनाज को डाइट में शामिल करें.
- घर पर जमा दही खाएं.
- ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में एक चम्मच घी जरूर लें.
- हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें और बाकी पूरे दिन भी शारीरिक गतिविधि करें.
- रोजाना सोने और जागने का टाइम फिक्स करें.
- गैरजरूरी स्क्रीन टाइम यानी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल आदि को घटाएं.

भारत की जाति व्यवस्था क्या है?

भारत की जाति व्यवस्था दुनिया के जीवित सामाजिक स्तरीकरण के सबसे पुराने रूपों में से एक है। बीबीसी इसकी जटिलताएँ समझाता है। वह प्रणाली जो हिंदुओं को उनके कर्म (काम) और धर्म (धर्म के लिए हिंदी शब्द, लेकिन यहां इसका अर्थ कर्तव्य है) के आधार पर कठोर पदानुक्रमित समूहों में विभाजित करती है, आमतौर पर 3,000 साल से अधिक पुरानी मानी जाती है।

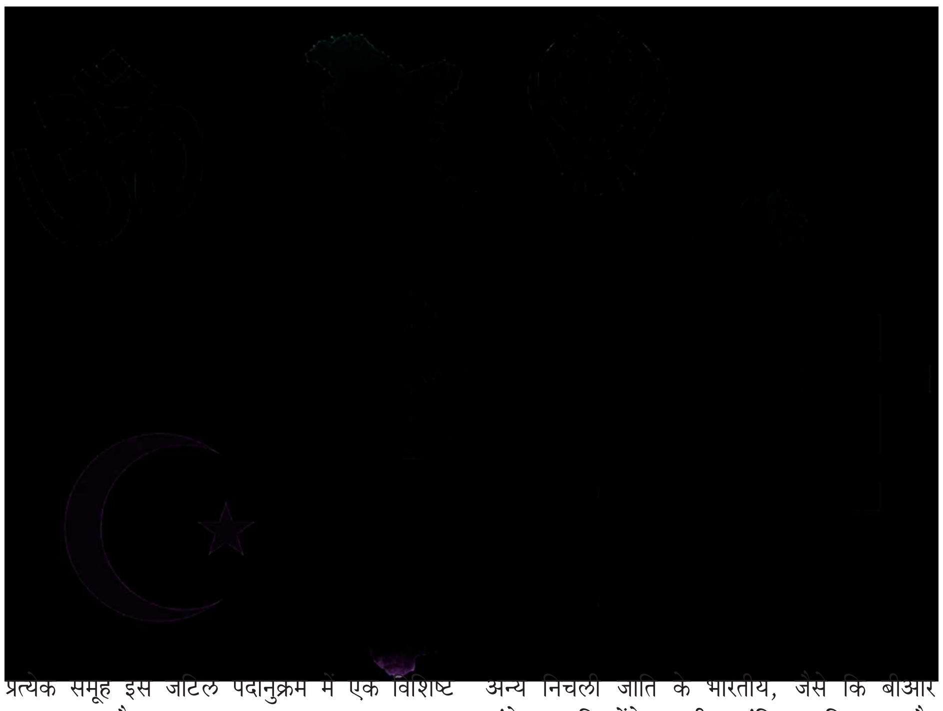

जाति की उत्पत्ति कैसे हुई?

मनुस्मृति , जिसे व्यापक रूप से हिंदू कानून पर सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक पुस्तक माना जाता है और ईसा मसीह के जन्म से कम से कम 1,000 साल पहले की है, 'समाज की व्यवस्था और नियमितता के आधार के रूप में जाति व्यवस्था को स्वीकार करती है और उचित ठहराती है'।

जाति व्यवस्था हिंदुओं को चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती है - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कई लोग मानते हैं कि समूहों की उत्पत्ति सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा से हुई है।

पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण थे जो मुख्य रूप से शिक्षक और बुद्धिजीवी थे और माना जाता है कि वे ब्रह्मा के मुख से आए थे। फिर कथित तौर पर उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, या योद्धा और शासक आए। तीसरा स्थान वैश्यों या व्यापारियों को मिला, जो उसकी जाँघों से निर्मित हुए थे। ढेर के निचले भाग में शूद्र थे, जो ब्रह्मा के चरणों से आए थे और सभी छोटे-मोटे काम करते थे।

मुख्य जातियों को उनके विशिष्ट व्यवसाय के आधार पर लगभग 3,000 जातियों और 25,000 उप-जातियों में विभाजित किया गया था।

इस हिंदू जाति व्यवस्था के बाहर अछूत - दलित या अछूत थे।

जाति कैसे काम करती है?

सदियों से, जाति ने हिंदू धार्मिक और सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू को निर्धारित किया है, प्रत्येक समूह इस जटिल पदानुक्रम में एक विशिष्ट स्थान रखता है।

ग्रामीण समुदायों को लंबे समय से जातियों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है - ऊंची और निचली जातियां लगभग हमेशा अलग-अलग कॉलोनियों में रहती थीं, पानी के कुएं साझा नहीं किए जाते थे, ब्राह्मण शूद्रों से भोजन या पेय स्वीकार नहीं करते थे, और कोई केवल अपनी जाति के भीतर ही शादी कर सकता था। .

इस प्रणाली ने उच्च जातियों को कई विशेषाधिकार प्रदान किए जबकि विशेषाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा निचली जातियों के दमन को मंजूरी दी गई।

अक्सर अन्यायपूर्ण और प्रतिगामी होने के लिए आलोचना की जाती है, यह सदियों तक लगभग अपरिवर्तित रहा, जिससे लोगों को निश्चित सामाजिक व्यवस्था में फँसाया गया जहाँ से बचना असंभव था।

हालाँकि, बाधाओं के बावजूद, कुछ दलित और अन्य निचली जाति के भारतीय, जैसे कि बीआर अंबेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा, और केआर नारायणन जो देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने, देश में प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हुए हैं।

हालांकि, इतिहासकारों का कहना है कि 18वीं शताब्दी तक, भारतीयों के लिए जाति के औपचारिक भेद सीमित महत्व के थे, सामाजिक पहचान बहुत अधिक लचीली थीं और लोग एक जाति से दूसरी जाति में आसानी से जा सकते थे।

नए शोध से पता चलता है कि कठोर सीमाएँ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा निर्धारित की गई थीं, जिन्होंने जाति को भारत की परिभाषित सामाजिक विशेषता बना दिया था, जब उन्होंने प्रणाली को सरल बनाने के लिए जनगणना का उपयोग किया था, मुख्य रूप से एक सामान्य कानून के साथ एकल समाज बनाने के लिए जिसे आसानी से शासित किया जा सकता था।

क्या सिस्टम कानूनी है?

स्वतंत्र भारत के संविधान ने जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया, और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और पारंपरिक रूप से वंचितों को समान अवसर प्रदान करने के प्रयास में, अधिकारियों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सबसे कम कोटा की घोषणा की। 1950 में जाति पदानुक्रम। 1989 में, ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नामक एक समूह को शामिल करने के लिए कोटा बढ़ाया गया था, जो पारंपरिक उच्च जातियों और निम्नतम के बीच आता है। हाल के दशकों में, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रसार और बढ़ते शहरीकरण के साथ, जाति का प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया है, खासकर शहरों में जहां विभिन्न जातियां एक साथ रहती हैं और अंतरजातीय विवाह आम होते जा रहे हैं। कुछ दक्षिणी राज्यों और उत्तरी राज्य बिहार में, कई लोगों ने सामाजिक सुधार आंदोलनों के बाद सिर्फ एक नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालाँकि परिवर्तनों के बावजूद, जाति की पहचान मजबूत बनी हुई है, और उपनाम लगभग हमेशा इस बात का संकेत होते हैं कि कोई व्यक्ति किस जाति का है।

नौकरी कोटा के बारे में क्या?

हाल के वर्षों में, कई समुदायों द्वारा ओबीसी के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की गई है - 2016 में हरियाणा में जाट समुदाय द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे और पटेल समुदाय ने 2015 में जाति कोटा तक पहुंच की मांग को लेकर गुजरात में बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। दोनों समृद्ध और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय हैं, लेकिन वे यह कहकर जातिगत आरक्षण की अपनी मांग का समर्थन करते हैं कि उनके समुदायों में बड़ी संख्या में लोग गरीब और पीड़ित हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि यदि राजनेताओं द्वारा नियमित रूप से आग को हवा नहीं दी जाती तो जाति व्यवस्था अब तक गायब हो गई होती।

चीन की षड़यंत्रकारी कब्जा करो की नीति से विश्व भी परेशान

पेज 1 का शेष

दिसंबर के मध्य में, यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (डीआईए) ने अपने वार्षिक रक्षा खुफिया सूचना प्रणाली विभाग के विश्वव्यापी सम्मेलन की मेजबानी की, जिसे DoDIIS के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न रक्षा विभाग (डीओडी) और डीआईए विभाग के प्रमुख, खुफिया समुदाय के नेता, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के फाइव आईज (एफवीईवाई) समुदाय के नेता एक साथ आए। उपस्थित लोगों में विभिन्न अमेरिकी वर्दीधारी सेवाओं के ध्वज अधिकारी भी शामिल थे जिन्होंने 'अराजकता से स्पष्टता - उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने' की थीम पर उद्योग से बात की। इस सम्मानित समुदाय की चिंताओं में मुख्य चिंता चीन द्वारा सुरक्षा के लिए लगातार बढ़ता खतरा था।

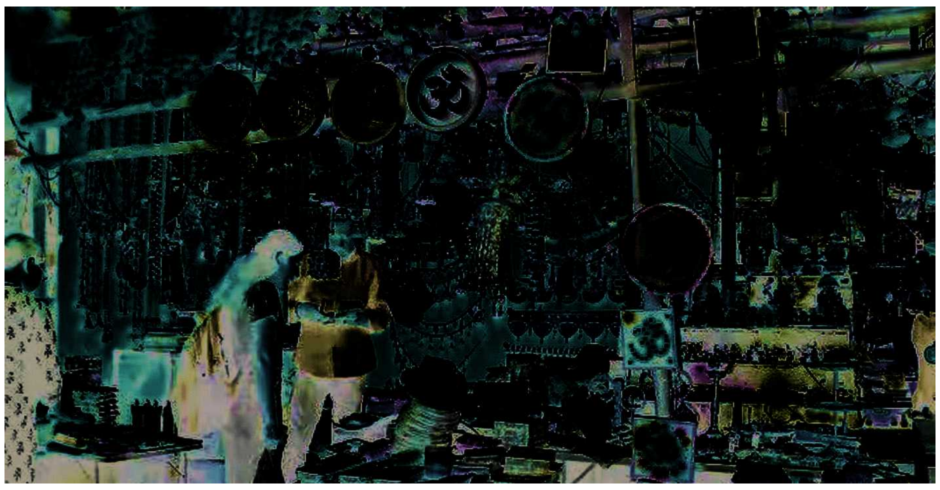

जबकि अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन की बात चल रही थी, मेरी मुख्य बात यह थी कि चीन को सभी प्रकार के उद्योगों के लिए वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में एक प्रमुख चिंता का विषय होना चाहिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, रक्षा और खुफिया में शामिल उद्योगों के लिए और आपूर्ति श्रृंखला।

साइबर सुरक्षा के खेल में अराजकता चीन की सहयोगी है

संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अराजकता चीन का सहयोगी है; वास्तव में, अराजकता व्यवधान के अवसर प्रस्तुत करती है। नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी (एनजीए) के निदेशक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में चीन द्वारा पेश की गई बढ़ती चुनौती के बारे में बात करते हुए कहा कि एआई की व्यावसायिक क्षमताएं ऐसे विरोधी राष्ट्र-राज्यों को वाणिज्यिक निर्माण के लिए आवश्यक गतिशील विश्लेषण पूरा करने में मदद करेंगी। ऑफ-द-शेल्फ आक्रमण समाधान।

चर्चा में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से बौद्धिक संपदा रहस्य हासिल करने की चीन की भूख पर भी चर्चा हुई। कई लोगों ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसने अपना विमान बनाते समय एफ-22 लड़ाकू जेट से संबंधित रहस्यों को छिपा लिया है। दरअसल, चीन का J-20 स्टील्थ फाइटर इस बात का उदाहरण है कि चीन जो कुछ इकट्ठा करता है उसका उपयोग कैसे करता है। अमेरिकी सैन्य क्षेत्र के इस लक्ष्यीकरण को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, जिसमें अमेरिकी वर्गीकृत जानकारी तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों के अभियोग, दोषसिद्धि और सजा भी शामिल है, जिन्होंने इसे चीनी खुफिया अधिकारियों के साथ साझा करने का विकल्प चुना है।

चीन विक्रेताओं के माध्यम से सैन्य खुफिया जानकारी को निशाना बनाता है

जीई एयरोस्पेस और अन्य एयरोस्पेस कंपनियों को लक्षित करने सहित, विक्रेताओं के माध्यम से पश्चिमी विमानन को लक्षित करने के चीन के ठोस प्रयास को देखने के लिए हमें बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर पूर्व नाटो लड़ाकू पायलटों को 'उड़ान' सिखाने के लिए चीन में लगातार निशाना बनाया जा रहा है और लालच दिया जा रहा है।

इनमें से कुछ पूर्व पायलटों ने खुद को नियंत्रित प्रौद्योगिकियों के अनधिकृत साझाकरण के लिए अभियोजन के गलत पक्ष में पाया है। कुछ देशों ने चेतावनियाँ जारी करने का सहारा लिया है, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दोनों के मामले में था। दोनों ने अपने पूर्व सैन्य पायलटों को याद दिलाया कि वे अपनी-अपनी वायु सेना में रहते हुए सीखे गए रहस्यों की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

बहुत अधिक निंदक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैंने चेतावनी पढ़ी तो मेरा पहला विचार था, 'हाँ, ठीक है।' चीन के लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित करने का अनुबंध स्वीकार करने वाला कोई भी पूर्व नाटो पायलट अच्छी तरह से जानता है कि वे चीन को बौद्धिक लाभ प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर कर रहे हैं, भले ही वे मिशन वक्तव्य को कितना भी अस्पष्ट क्यों न करें। यह बौद्धिक लाभ, ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता है, जो रक्षा क्षेत्र के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाती है। DoDIIS में परिचालन सुरक्षा में निवेश करने की आवश्यकता, सांसारिक निजी रखने की आवश्यकता और किसी की गतिविधियों के बारे में सोशल नेटवर्क साइटों पर बहुत अधिक जानकारी साझा करने से बचने की आवश्यकता का उल्लेख एक से अधिक बार किया गया था।

सरकारी-कॉर्पोरेट भागीदारी साइबर-लचीलेपन की कुंजी है

जब संघर्ष होता है, तो साइबर-लचीलेपन को बढ़ावा देने वाले रिश्ते बनाना शुरू करने में बहुत देर हो चुकी होती है। शांत समय में, एजेंसियों और सीमाओं के पार जानकारी साझा करना अब आवश्यक है। प्रौद्योगिकी वहां है, इच्छाशक्ति वहां है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खुफिया जानकारी साझा करने को अधिक नियमित वास्तविकता बनाने के लिए नीति में कुछ मामूली समायोजन की आवश्यकता होगी। मध्य-स्तर की नौकरशाही अक्सर सीमाओं के पार संबंध बनाने के रास्ते में आ जाती है। जैसा कि मेरे ऋषि पिता कहते थे, हमारे सिस्टम में कब्ज़ हो जाता है जब मध्यम श्रेणी के अधिकारी इस डर से निर्णय लेने में झिझकते हैं कि इसका उल्टा असर होगा और उनके करियर की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी।

साप्ताहिक समय माया

क्षेत्रीय ग्रामीण सड़क प्राधिकरण आयातित डकैतों का अड्डा

सड़क सेस, एडीबी, विश्व बैंक के ऋण के बाद भी सड़कें स्तरहीन

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर भ्रष्टों को जानकारी न देने बहानों का अंबार

भारत सरकार अटल बिहारी की सरकार के समय सन 2000 से पेट्रोल-डीजल-गैस के साथ अन्य वस्तुओं व अधिकांश सेवाओं पर सड़क सेस के रूप में 2% की लाखों करोड़ की वसूली कर रही है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रामीण संरचना विकास के नाम पर वह एशियाई विकास बैंक का ऋण भी लेकर भ्रष्टाचार कर रही है। पीएमजीएसवाइ का मध्य प्रदेश में यह काम मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण सड़क प्राधिकरण कर रहा है जिसमें सारे आयातित इंजीनियर जो कि ग्रामीण विकास के ग्रामीण यांत्रिकीय से, विद्युत मंडल लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय मध्य प्रदेश जल संसाधन व अन्य विभागों से आयातित प्रति नियुक्ति पर, सेवा निवृत्ति के बाद नियुक्त किए जाते हैं। स्वाभाविक है अधिकांश घोर भ्रष्ट जालसाजों का समूह होता है।

बेशक इस प्राधिकरण में केंद्रीय सरकार का सारा काम होता है इसलिए वहां की कार्य पद्धति उसी तरीके की होती है। परंतु ग्रामीण विकास विभाग जैसे घोर भ्रष्ट विभाग से आया हुआ ओ.पी. दशोरा जो वर्तमान में इंदौर-उज्जैन संभाग के 15 जिलों का मुख्य महाप्रबंधक है? हरामखोर से सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने पर बहाने बनाने चाही गई जानकारी धारा 4 के अंतर्गत साइट पर अपलोड ना करने, धारा 6(3)iii का उल्लंघन कर दलीलें देने का विशेषज्ञ है। ताकि जानकारी के आवेदन का पत्र अंतरण जिसमें जानकारी अपने अधीनस्थ इकाइयों में कार्यरत महाप्रबंधकों से लेनी है। जो महीना 20 से ज्यादा परियोजना क्रियान्वयन इकाई के महा प्रबंधकों से आ रहा है। वह बंद ना हो जाए अंतरित नहीं करता। जब अपील लगाई जाती हैं। तो उनको रद्द कर देता है।

इसलिए जानबूझकर इन हरामखोर जालसाजों ने हीं जिला स्तर की क्रियान्वयन इकाइयों के कार्यालयों के पूरे पते तक नहीं डाले हैं। चुंकि सारा विभाग ही आयातित है। जिला स्तर की अधिकांश इकाइयां किराये के मकानों में अंतरित की जाकर चलाई जाती हैं।

एक तरफ पूरे पता न होने के कारण लिफाफा लौट आता है और दूसरी तरफ जानबूझकर हरामखोर जलसा आज सूचना के अधिकार के पात्रों के लिए लिफाफे लेने से ही मना कर देते हैं क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार है और जिस स्तर पर सड़क निर्माण और रख-रखाव नियमानुसार कार्य होना चाहिए वह ना किया जाकर जानबूझकर स्तरहीन काम करवा कर परफॉर्मेंस गारंटी पीरियड को पूरा किया जाता है। इंडियन रोड कांग्रेस की 2012, 16, 22 स्वभाव में स्पष्ट ढंग से बोला गया था। कि पूरे देश भर के गांवों 68% गांवों में भी जहां दो फसलें भी अगर वर्ष में अच्छी आ जाती हैं। वहां पर न केवल मोटर साइकिलों ट्रैक्टरों कारों की आवाज यही बढ़ जाने से हर सड़क कम से कम 6 से 9 मीटर की होनी चाहिए ताकि गांवों में कम चौड़ी सड़कों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जिस पर ध्यान नहीं देगा दूसरी तरफ अगर गांवों के आजू-बाजू में अच्छी गिट्टी, मिट्टी, पत्थर, रेती की खदानें हैं। तो वहां पर आने जाने वाले डंपर ट्रैक्टर वहां की सड़कों को भारी वजन के कारण बर्बाद कर रहे हैं। पर जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का स्तर है। उसे स्टार में भी भारी भ्रष्टाचार किया जाता है किसी भी सड़क के निर्माण की प्रक्रिया और उसकी मिट्टी और स्तर की निर्माण की जांच व परीक्षण करने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी जाट करवानी चाहिए जैसे कि विभाग में डीपीआर और अन्य कार्यों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है।

वैसे ही निर्माण के उपरांत उनकी जांच की सच्चाई को समझने के लिए अलग से एजेंसी की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि अगर में बैठे विष्णु प्रसाद टेंटवाल, अलीराजपुर में मयंक तिवारी बड़वानी में मयंक तिवारी बुरहानपुर में डीके त्रिपाठी देवास एक व दो में जीवन कुमार गुप्ता धार में एक और तीन में अनुपम सक्सैना धार दो में मयंक तिवारी इंदौर में लोकेंद्रसिंह मंडलोई झाबुआ में अनुपम सक्सेना, खंडवा में इं. डीके त्रिपाठी अतिरिक्त प्रभार, खरगोन 1 व 2 में इं. हरिप्रसाद जाटव मंदसौर-नीमच में इं. तोविंदर सिंह जोहेर, रतलाम में तोविंदर सिंह जोहेर अर्थात तीन इकाइयों का शाजापुर में संजय श्रीवास्तव, उज्जैन एक और दो में शमीम खान बैठे हुए हैं अधिकांश के पास दो -3 इकाइयों के प्रभार हैं।

जबकि हर इकाई में सैकड़ो किलोमीटर की सड़के निर्माणाधीन या रख-रखाव में है। देश में चारों तरफ वर्तमान में दो करोड़ से ज्यादा इंजीनियर बेकार है। परंतु विभागों में वर्षों से भर्ती न होने के कारण पर्याप्त इंजीनियर और कर्मचारियों के अभाव होने से कार्यों के लंबित होने न्यायालय में उलझने से भ्रष्टाचार के साथ कार्य की स्तरहीनता के साथ बिगड़ना भी स्वाभाविक है।

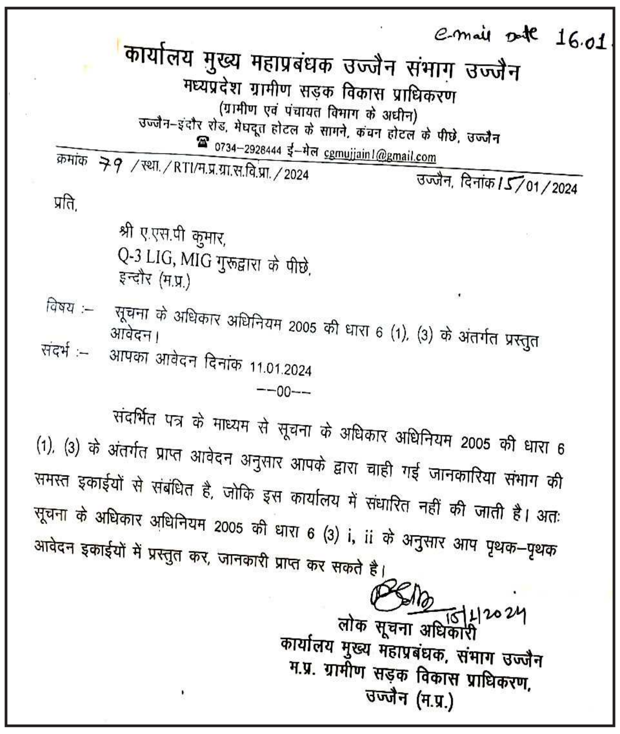

e-mail date 16.01

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक उज्जैन संभाग उज्जैन
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
(ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के अधीन)
उज्जैन-इंदौर रोड, मेघदूत होटल के सामने, कंचन होटल के पीछे, उज्जैन
☎ 0734-2928444 ई-मेल cgmujjain1@gmail.com

क्रमांक 79 /स्था./RTI/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा./2024 — उज्जैन, दिनांक 15/01/2024

प्रति,
श्री ए.एस.पी कुमार,
Q-3 LIG, MIG गुरूद्वारा के पीछे,
इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1), (3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।
संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 11.01.2024

--00--

संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1), (3) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन अनुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारिया संभाग की समस्त इकाईयों से संबंधित है, जोकि इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) i, ii के अनुसार आप पृथक-पृथक आवेदन इकाईयों में प्रस्तुत कर, जानकारी प्राप्त कर सकते है।

15/1/2024
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, संभाग उज्जैन
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
उज्जैन (म.प्र.)

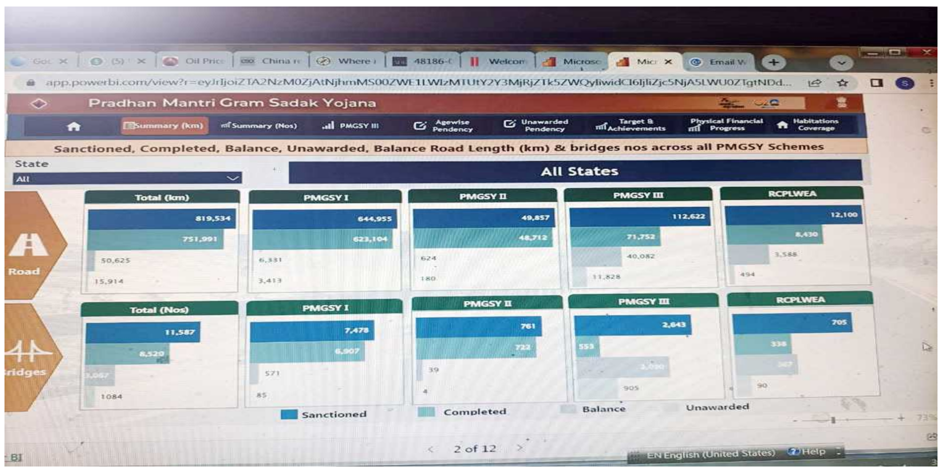

कार्टून कोना

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय: स्कंध पंजी नहीं रखते

जल जीवन मिशन के 44000 करोड रु. में अधिकांश खरीदी

सूचना के अधिकार में 18 वर्ष बाद भी भ्रष्टाचार छुपाने जानकारी अपलोड नहीं की जाती

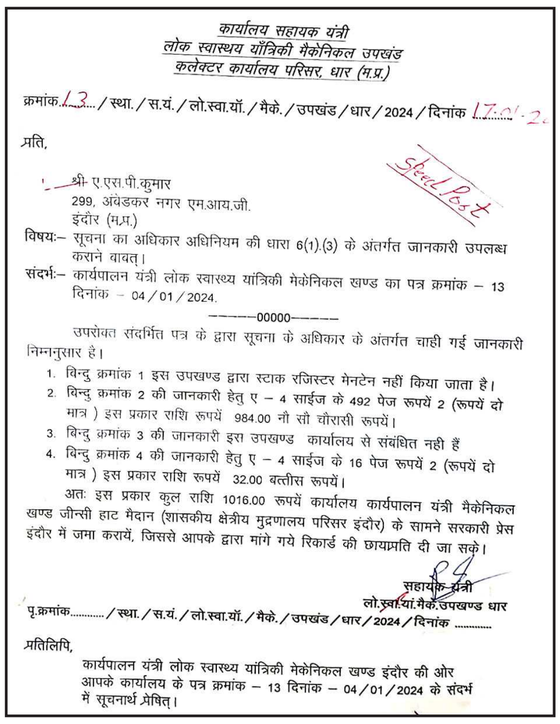

कार्यालय सहायक यंत्री
लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी मैकेनिकल उपखंड
कलेक्टर कार्यालय परिसर, धार (म.प्र.)

क्रमांक 13 / स्था. / स.यं. / लो.स्वा.यॉं. / मैके. / उपखंड / धार / 2024 / दिनांक 17.01.2024

प्रति,

श्री ए.एस.पी.कुमार
299, अंबेडकर नगर एम.आय.जी.
इंदौर (म.प्र.)

Speed Post

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1).(3) के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराने वावत्।

संदर्भः– कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकेनिकल खण्ड का पत्र क्रमांक – 13 दिनांक – 04 / 01 / 2024.

———00000———

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत चाही गई जानकारी निम्नानुसार है।

1. बिन्दु क्रमांक 1 इस उपखण्ड द्वारा स्टाक रजिस्टर मेनटेन नहीं किया जाता है।
2. बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी हेतु ए – 4 साईज के 492 पेज रूपयें 2 (रूपयें दो मात्र) इस प्रकार राशि रूपयें 984.00 नौ सौ चौरासी रूपयें।
3. बिन्दु क्रमांक 3 की जानकारी इस उपखण्ड कार्यालय से संबंधित नही हैं
4. बिन्दु क्रमांक 4 की जानकारी हेतु ए – 4 साईज के 16 पेज रूपयें 2 (रूपयें दो मात्र) इस प्रकार राशि रूपयें 32.00 बत्तीस रूपयें।

अतः इस प्रकार कुल राशि 1016.00 रूपयें कार्यालय कार्यपालन यंत्री मैकेनिकल खण्ड जीन्सी हाट मैदान (शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय परिसर इंदौर) के सामने सरकारी प्रेस इंदौर में जमा करायें, जिससे आपके द्वारा मांगे गये रिकार्ड की छायाप्रति दी जा सके।

सहायक यंत्री
लो.स्वा.यां.मैके.उपखण्ड धार

पृ.क्रमांक........../ स्था. / स.यं. / लो.स्वा.यॉं. / मैके. / उपखंड / धार / 2024 / दिनांक ....

प्रतिलिपि,
कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकेनिकल खण्ड इंदौर की ओर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक – 13 दिनांक – 04 / 01 / 2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

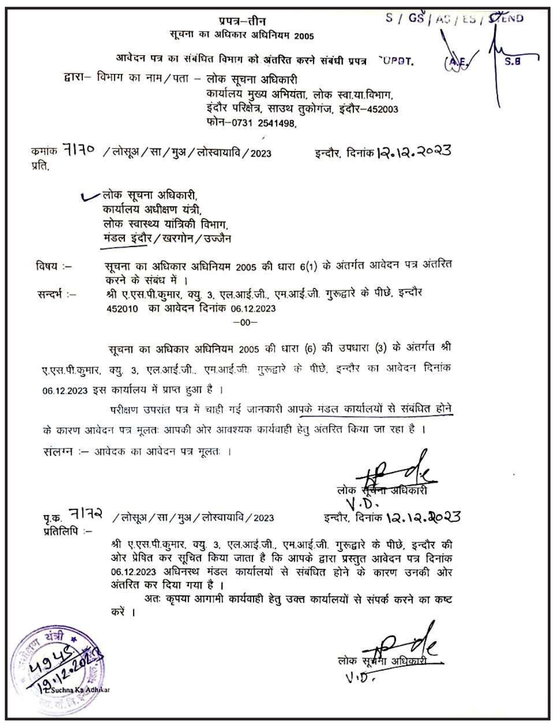

प्रपत्र–तीन
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

S / GS / AS / ES / STEND

आवेदन पत्र का संबंधित विभाग को अंतरित करने संबंधी प्रपत्र UPDT. A.E. S.B

द्वारा– विभाग का नाम / पता – लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वा.या.विभाग,
इंदौर परिक्षेत्र, साउथ तुकोगंज, इंदौर–452003
फोन–0731 2541498,

कमांक 7170 / लोसूअ / सा / मुअ / लोस्वायावि / 2023 इन्दौर, दिनांक 12.12.2023
प्रति,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंडल इंदौर / खरगोन / उज्जैन

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र अंतरित करने के संबंध में ।

सन्दर्भ :– श्री ए.एस.पी.कुमार, क्यु. 3, एल.आई.जी., एम.आई.जी. गुरूद्वारे के पीछे, इन्दौर 452010 का आवेदन दिनांक 06.12.2023

–00–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के अंतर्गत श्री ए.एस.पी.कुमार, क्यु. 3, एल.आई.जी., एम.आई.जी. गुरूद्वारे के पीछे, इन्दौर का आवेदन दिनांक 06.12.2023 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

परीक्षण उपरांत पत्र में चाही गई जानकारी आपके मंडल कार्यालयों से संबंधित होने के कारण आवेदन पत्र मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित किया जा रहा है ।

संलग्न :– आवेदक का आवेदन पत्र मूलतः ।

लोक सूचना अधिकारी
V.D.

पृ.क. 7172 / लोसूअ / सा / मुअ / लोस्वायावि / 2023 इन्दौर, दिनांक 12.12.2023
प्रतिलिपि :–

श्री ए.एस.पी.कुमार, क्यु. 3, एल.आई.जी., एम.आई.जी. गुरूद्वारे के पीछे, इन्दौर की ओर प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.12.2023 अधिनस्थ मंडल कार्यालयों से संबंधित होने के कारण उनकी ओर अंतरित कर दिया गया है ।

अतः कृपया आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालयों से संपर्क करने का कष्ट करें ।

4945 19.12.2023 Suchna Ka Adhikar

लोक सूचना अधिकारी
V.D.

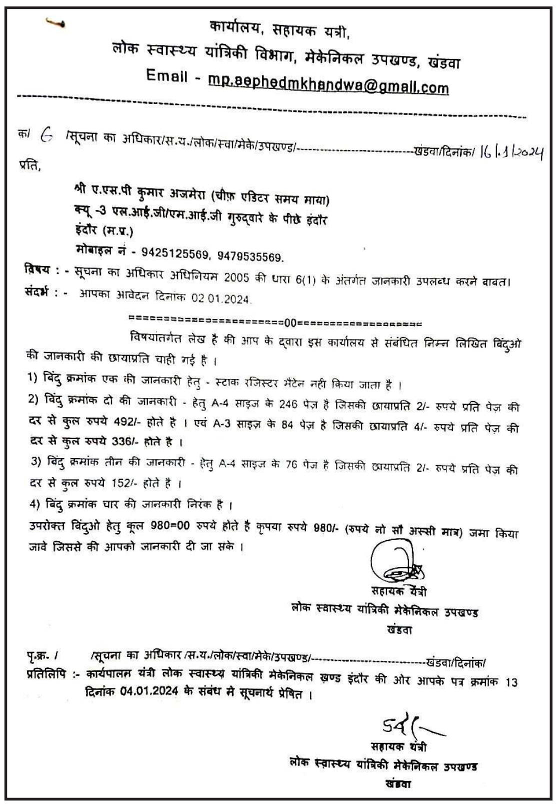

कार्यालय, सहायक यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मेकेनिकल उपखण्ड, खंडवा
Email - mp.aephedmkhandwa@gmail.com

क्र/ 6 /सूचना का अधिकार/स.य./लोक/स्वा/मेके/उपखण्ड/------------खंडवा/दिनांक/ 16/1/2024

प्रति,

श्री ए.एस.पी कुमार अजमेरा (चीफ़ एडिटर समय माया)
क्यू -3 एल.आई.जी/एम.आई.जी गुरुद्वारे के पीछे इंदौर
इंदौर (म.प्र.)
मोबाइल नं - 9425125569, 9479535569.

विषय : - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध करने बाबत।

संदर्भ : - आपका आवेदन दिनांक 02.01.2024.

=============00=============

विषयांतर्गत लेख है की आप के द्वारा इस कार्यालय से संबंधित निम्न लिखित विंदुओ की जानकारी की छायाप्रति चाही गई है ।

1) बिंदु क्रमांक एक की जानकारी हेतु - स्टाक रजिस्टर मैंटेन नही किया जाता है ।

2) विंदु क्रमांक दो की जानकारी - हेतु A-4 साइज के 246 पेज है जिसकी छायाप्रति 2/- रुपये प्रति पेज़ की दर से कुल रुपये 492/- होते है । एवं A-3 साइज़ के 84 पेज़ है जिसकी छायाप्रति 4/- रुपये प्रति पेज़ की दर से कुल रुपये 336/- होते है ।

3) विंदु क्रमांक तीन की जानकारी - हेतु A-4 साइज के 76 पेज है जिसकी छायाप्रति 2/- रुपये प्रति पेज़ की दर से कुल रुपये 152/- होते है ।

4) विंदु क्रमांक चार की जानकारी निरंक है ।

उपरोक्त विंदुओ हेतु कूल 980=00 रुपये होते है कृपया रुपये 980/- (रुपये नो सौ अस्सी मात्र) जमा किया जावे जिससे की आपको जानकारी दी जा सके ।

सहायक यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकेनिकल उपखण्ड
खंडवा

पृ.क्र- / /सूचना का अधिकार /स.य./लोक/स्वा/मेके/उपखण्ड/------------खंडवा/दिनांक/
प्रतिलिपि :- कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकेनिकल खण्ड इंदौर की ओर आपके पत्र क्रमांक 13 दिनांक 04.01.2024 के संबंध मे सूचनार्थ प्रेषित ।

सहायक यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकेनिकल उपखण्ड
खंडवा

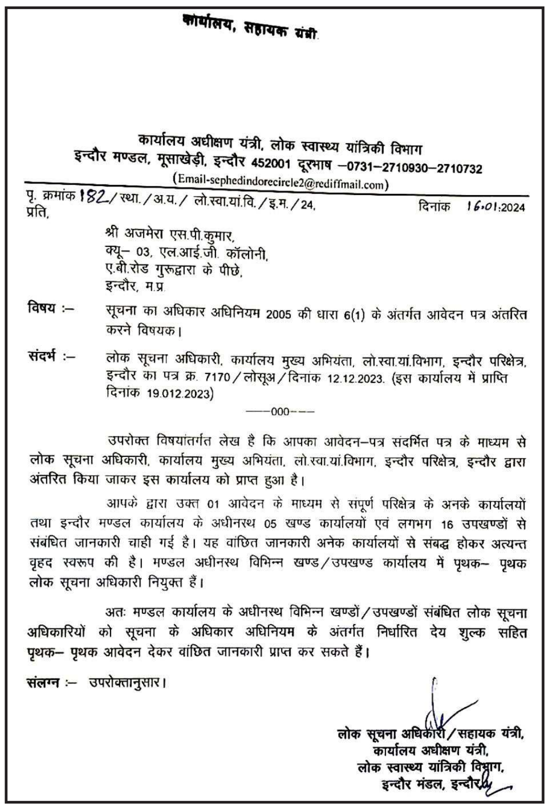

कार्यालय, सहायक यंत्री

कार्यालय अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्दौर मण्डल, मूसाखेड़ी, इन्दौर 452001 दूरभाष –0731–2710930–2710732
(Email-sephedindorecircle2@rediffmail.com)

पृ. क्रमांक 182 / स्था. / अ.य. / लो.स्वा.यां.वि. / इ.म. / 24, दिनांक 16.01.2024
प्रति,

श्री अजमेरा एस.पी.कुमार,
क्यू– 03, एल.आई.जी. कॉलोनी,
ए.बी.रोड गुरूद्वारा के पीछे,
इन्दौर, म.प्र.

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र अंतरित करने विषयक।

संदर्भ :– लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग, इन्दौर परिक्षेत्र, इन्दौर का पत्र क्र. 7170 / लोसूअ / दिनांक 12.12.2023. (इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 19.012.2023)

——000———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपका आवेदन–पत्र संदर्भित पत्र के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग, इन्दौर परिक्षेत्र, इन्दौर द्वारा अंतरित किया जाकर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

आपके द्वारा उक्त 01 आवेदन के माध्यम से संपूर्ण परिक्षेत्र के अनके कार्यालयों तथा इन्दौर मण्डल कार्यालय के अधीनस्थ 05 खण्ड कार्यालयों एवं लगभग 16 उपखण्डों से संबंधित जानकारी चाही गई है। यह वांछित जानकारी अनेक कार्यालयों से संबद्ध होकर अत्यन्त वृहद स्वरूप की है। मण्डल अधीनस्थ विभिन्न खण्ड / उपखण्ड कार्यालय में पृथक– पृथक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त हैं।

अतः मण्डल कार्यालय के अधीनस्थ विभिन्न खण्डों / उपखण्डों संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित देय शुल्क सहित पृथक– पृथक आवेदन देकर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

लोक सूचना अधिकारी / सहायक यंत्री,
कार्यालय अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
इन्दौर मंडल, इन्दौर

मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग जिसका मुख्य कार्य ग्रामीण से लेकर शहरी आबादी को पूरे प्रदेश मेंजनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में श्रीमती संपत्ति इसकी मंत्री हैं। प्रमुख सचिव संजय शुक्ला प्रमुख अभियंता संजय अंधवान हैं। जनता को जल पिलाने के नाम पर केंद्र सरकार ने 2019 से जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिसे सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल 2024 तक उपलब्ध करवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस विभाग में नल से जल आपूर्ति के लिए संभागों उप संभागों उपयंत्री कार्यालयों तक मोटर पाइप लाइन हैंड पंप सेट आदि की भोपाल स्तर पर प्रदेश के खंड कार्यालय में हजारों करोड़ की खरीदी की जाकर आपूर्ति होती है।

स्वाभाविक सी बात है, खरीदने 10 से 20% तक का कमीशन कार्यपालन यंत्री से प्रमुख अभियंता प्रमुख सचिव और मंत्री मुख्यमंत्री तक जाता है।

वर्तमान में आहरण और संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यपालन यंत्री ही सबसे महत्वपूर्ण होने के साथ वह ही सारी खरीदी के बिलों को भुगतान करता है, पर आश्चर्य की बात यह है पिछले 18 सालों से इस विभाग से स्टॉक रजिस्टर या स्कंद पंजी की मांग की जा रही है। पर यहां बैठे सारे हरामखोर चाहे वह उज्जैन के सिंहस्थ का नायक सुनील उदिया हो जो वर्तमान में इंदौर में पिछले 5 सालों से जमा हुआ है या इंदौर नर्मदा जल आपूर्ति के संभाग दो में बैठा संजीव श्रीवास्तव जो पिछले 20 साल से इंदौर में है। हर वर्ष सैकड़ों करोड़ का भुगतान करता है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर सारे भ्रष्ट जलशा आज जानकारी देने की अपेक्षा स्पष्ट पत्रों में लिख देते हैं हमारे यहां स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता। क्यों अपने आप की जागीर है। जिसमें तत्काल प्राप्त हुए उत्तरों में इंदौर संभाग के विद्युत यांत्रिकीय उपखंडों इंदौर-खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ से प्राप्त जवाबों में स्पष्ट लिखा गया है कि हमारे यहां स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। पहले खरीदी में कमीशन के साथ स्तरहीन माल खरीदने, रखरखाव फिर उसके वितरण में, हर कदम पर भ्रष्टाचार किया जाता है। रखे हुए माल को पुराने माल से बदलकर कमीशन खा जाना आवंटित माल को बेंच के खा जाना। यथार्थ में हर संस्थान में स्टॉक सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का अड्डा होता है और क्योंकि खरीदी बिक्री से लेकर स्टॉक के रखरखाव में भी भारी भ्रष्टाचार और जालसाजी की जाती है इसलिए यह हरामखोर न केवल प्रदेश के 65 से ज्यादा संभागों के डेढ़ सौ से ज्यादा उपसंभागों में सभी प्रकार के स्टॉक में भारी भ्रष्टाचार किए जाने माल कम पाए जाने खरीदी कम किए जाने के कारण कोई भी स्टॉक रजिस्टर दिखने पता नहीं जानकारी देने में तैयार नहीं होता और उसके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए न केवल कार्यपालन यंत्री, अधीक्षक यंत्री, मुख्य अभियंता से प्रमुख अभियंता तक सब आंख खींचकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने स्टॉक रजिस्टर की कॉपी देने से मना कर देते हैं?

दूसरी तरफ अधिकांश पूरे प्रदेश में इस विभाग में भी प्रभार दो प्रभारों का खेल चल रहा है, इसलिए अधिकांश प्रभारी को भी उच्च पद का प्रभार देकर एक तरफ वसूली की जा रही है, दूसरी तरफ उनका शोषण किया जा रहा है, जिसे वर्तमान मुख्यमंत्री को शीघ्र बदलना चाहिए और स्थाई पदोन्नतियां देकर अधिकारियों-कर्मचारियों को व्यवस्थित करना चाहिए। इस विभाग में भी भ्रष्टाचारियों का बोलबाला तो है ही यहां पर भी अजय श्रीवास्तव जो पूर्व में कई बार निलंबित किया जा चुके हैं अधीक्षण यंत्री के रूप में पदस्थ किए गए हैं।

मुख्य अभियंता कार्यालय को सूचना के अधिकार में एक पत्र दिया था। इसके संबंध में वहां के लोग सूचना अधिकारी ने धारा 63 के अंतर्गत अपने तीन अधीनस्थ अधीक्षण यंत्रियों उज्जैन, इंदौर और खरगोन को अंतरित किया, परंतु खरगोन ने जवाब नहीं दिया। इंदौर ने अपने भ्रष्टाचार और जालसाजियों को छुपाने और अपने अधीनस्थ कार्यपालन यंत्रियों से महीना वसुलने के कारण यहीं से पत्र लौटा दिया। बेशक उज्जैन के अधीक्षण यंत्री खुराना जी ने उसको वरिष्ठ कार्यालय के आदेश अनुसार अपने संभागों को भेजा। वैसे भी अधिकांश संभागों में प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों को ही महीने की ईएमआई पर ही पदस्थ किया गया है। इसलिए अपील लगाने पर उनके वरिष्ठ कार्यालय अपने अधीन वस्तुओं को बचाने का हर संभव प्रयास करता है और अजय श्रीवास्तव का इतिहास है। पिछले 3 सालों में कभी भी किसी भी अपील करने का अपनी वसूली करने ईमानदारी से कभी नहीं किया और ना ही जानकारी दिलवाई।

जनधन की लूट मची है
लूट सके तो लूट
अंत काल पछताएगा
जब सत्ता जाएगी छूट

भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था को किया बर्बाद

पेज 8 का शेष

हमारे बुजुर्गों के पास अपने अनुभवों और ज्ञान का भंडार होता था। जो सहज में ही बच्चों को बिना किसी विद्यालय में जाए मिल जाया करता था?।

संयुक्त परिवारों में जातिगत पुस्तैनी धंधे व्यवसाय को सहज में बचपन से ही सीखने समझने और उसको उत्पादक बनाने में आने वाली पीढ़ी ज्यादा परिष्कृत होकर कार्य को संपन्न करते हुए पीढी दर पीढ़ी बिना किसी रोजगार की अतिरिक्त मांग किए हुए करती चली आ रही थी। उसे सस्ते श्रमिक पाने देश के जातिगत पुस्तैनी व्यवसाय को खत्म करने और अपना माल बेचने, किए गए सारे षड्यंत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सफल बना मोटी कमाई भी कर ली। परंतु मनुष्य के जीवन की प्राथमिक आवश्यकता परिवार और उसमें भी संयुक्त परिवार जो अब बिरले सौभाग्य शाली लोगों को ही मिल पाता है। को खत्म करने से हर व्यक्ति आर्थिक सामाजिक नैतिक रूप से पतन की ओर अग्रसर हुआ। जिसने यथॉर्थ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नुकसान ज्यादा पहुंचाया।

अब छोटे परिवारों में एकाकीपन को दूर करने आत्महत्या तलाक के मामलों को रोकने, बेरोजगारी खत्म करने आर्थिक सामाजिक रूप फिर मजबूत बनाने अब विदेशी सामाजिक संगठन भी यूरोप के देशों में संयुक्त परिवारों मेंजीवनजीने को बढ़ावा दे रहे हैं।

अब वही विश्व घातक संगठन व उसकी धन देने वाली कंपनियां भी परिवारों को संयुक्त बनाने मजबूत करने की बात करने लगा है। क्योंकि सबका अंतिम उपदेशधन कमाना है दूसरी युक्त परिवार में आर्थिक रूप से मजबूती देने के साथ लोग ज्यादा बड़े निवेश करने, बड़े दांव लगाने, खरीदी करने की जोखिम में धन झोंकने को तैयार रहते हैं।

मैं विश्वास करने लगे हैंजबकि एकल परिवारों में लोग अपनी छोटी सी आय मेंअपने ही भरण पोषण निवास की व्यवस्था करने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ही जीवन पूरा कर डालते हैं। जबकि संयुक्त परिवारों में लोगों की छोटी कमाई में भी जीवन की आवश्यकताओं को सीमित कर की गई छोटी बचतों से भी बड़ी जोखिम परिवार के सदस्य एक दूसरे के सहारे उठाने से नहीं चूकते। संयुक्त परिवारों में घर के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति समर्पण सम्मान एक दूसरे कोआर्थिक सामाजिक नैतिक रूप से मजबूत करने के साथ बीमारी दुख परेशानियों विपन्नताओं में भी मानसिक रूप से टूटने नहीं देता जो मनुष्य की बड़ी सफलताओं में काम आता है। संयुक्त परिवारों से समाज मजबूत होता है तो दूसरी तरफ इससे राष्ट्र के विकास को भी गति मिलती है।

आप विदेशी लेखक भी मानते हैं। कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने माल को बेचने उससे मोटी कमाई करने भारी 24 घंटे टीवी मोबाइल नंबरभारी भरकम विज्ञापन पर खर्च करने से घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए। जिसने परिवारों से लेकर बच्चों के भविष्य को अत्यधिक गहरा एकाकीपन और अवसाद का झटका दिया है।

जिससे परिवार और समाज टूटने लगे और उसकी कुल सकल हानि राष्ट्र की सरकारों को बुजुर्गों को संभालने से लेकर बच्चों के संभालने तक में सामाजिक आर्थिक छाती का दुष्प्रभाव और राष्ट्रों को अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्थाओं पर खर्च कर भोगना पड़ रहा है। जिसका भुगतान करों के रूप में सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय लोगों को करना पड़ रहा है। जिसके लिएऔर राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर परभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने षडयंत्रों के कारण जिम्मेदार हैं।

साप्ताहिक समय माया

बहुराष्ट्रीय कंपनियों व ईसाई मिशनरियों के षड़यंत्रों ने

भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था को किया बर्बाद

एकाकी पन से अवसाद, बेरोजगारी, आत्महत्या, तलाक से बिगड़ रहे परिवार और समाज

भारत में प्राचीन काल से सनातनियों के सभी घटकों जातियों में एकजुट संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। जिसे भारत में आकर शकों व मुस्लिम शासकों ने बर्बाद नहीं कर सके। उसे अंग्रेजों और उनकी ईसाई

मिशनरियों ने संयुक्त परिवारों की एकजुटता को खत्म कर कमजोर करने व ईसाई धर्म फैलाने के लिए हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की और उसमें वह सफल भी रहे और ईसाई धर्म के पैर भारत में जमा दिए। सन 1930 से लेकर 50 तक ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने वाले 55 से ज्यादा देशों जिसमें भारत भी एक देश था। जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की आर्थिक हालत कमजोर होने व नौसेना के भारतीय जवानों द्वारा अंग्रेज 300 से ज्यादा नौसैना अधिकारियों की हत्याएं करने नौकायें डूबोने से डरकर देश छोड़कर जाने पर पट्टे के दस्तावेज हस्ताक्षर करवा नेहरू गांधी को देश सौंप दिया था।

आजादी के बाद इस काम को अंजाम देने के लिए विश्व घातक स्वास्थ्य संगठन जो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि निर्माता उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के धन से चलने वाली विक्रय प्रबंधन संस्था ने सुनियोजित षडयंत्र के अंतर्गत 'एकल परिवार सुखी परिवार', 'दो बच्चे, सबसे अच्छे', 'हम दो हमारे दो', 'छोटा परिवार सुखी परिवार', के नारे दे और बच्चों के जन्म को रोकने सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव को बढ़ावा दे वहीं परपैसे देकर नसबंदी करने का जो षड़यंत्र किया उसने हिंदू समाज व उसके सभी घटकों को आत्यधिक आर्थिक सामाजिक और नैतिक रूप से कमजोर किया। यही कारण थाकि हिंदुओं कीजन्म दर 1970 के बाद सेलगातार गिरने लगी जो हिंदू आजादी के समय 30 करोड़ थे वह संदर्भ 2021 तक मात्र 90 करोड़ हुए परंतु आजादी के समय जो 3 करोड़

मुसलमान थे वह विश्व घातक संगठन के किसी भी बहकावे आर्थिक लालच और नारों से प्रभावित नहीं हुए और वह अपने यहां कुंवारे लड़के लड़कियों की अवयस्कों की शादियां, पुरुषों द्वारा 2 से 5 शादियां कर संयुक्त परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने के साथ अधिकतम बच्चे पैदा करने में न केवल देश में वरन दुनिया के ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया रूस में लगे रह सतत जनसंख्या विस्तार कर रहे हैं। जो भारत में ही 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। दूसरी तरफ सनातनियों के ब्राह्मण बनियों क्षत्रियों में लगातार इन नारों के कारण सतत90 के बाद सेजनसंख्या घाटी चली जा रही है और कुछ घटक जैन जो कुल आबादी के 1%भी नहीं हैं। माहेश्वरियों, ब्राह्मणों, राजपूतों को सबसे ज्यादा समाज की जन्म दर घटने से हानि हो समाज लुप्त हो रही है। भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था आर्थिक सामाजिक नैतिक रूप से हर तरह से मजबूत हुआ करती थी। घरेलू जातिगत व्यवसायों के साथ कृषि आदि में पीढ़ी दर पीढ़ी बिना बेरोजगारी के परिवार एकजुट रहकर फलते फूलते रहते थे। परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में अपने माल को प्रचलित करने बैंचने अधिकतम व्यवसाय करने इन संयुक्त परिवारों को हर तरह से तोड़ दिया। अब छोटे परिवारों में एकाकी पन के कारण बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अकेले रहने के कारण अवसाद से उत्पन्न रक्तचाप ह्रदयाघात की बीमारियों, आत्महत्या से मौतें होने, परिवार बिखरने के कारण सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर भारी दुष्प्रभाव पड़ा। संयुक्त परिवारों में माता-पिता के काम पर चले जाने के बाद में भी घर में ज्यादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची व उनके बच्चों के परिवार के साथ रहने से बच्चों को एकाकीपन में सूचना होने के साथ सामाजिक रीति रिवाज परंपरायें जीवन जीने के सबके साथ रहने के सामाजिक नैतिक तौर तरीके का आंख खुलते ही अवसर मिल जाता था।

(शेष पेज 7 पर)

जनता को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर निकलना होगा

कम्यूनिस्टों का आंदोलन जनता के हकों की लड़ाई

लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूर किसान आदिवासियों ने 26 जनवरी को वाहन जत्था निकला

गणतंत्र दिवस पर सयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान के तहत लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूर किसान आदिवासियों ने 26 जनवरी को वाहन जत्था निकला।

मोदी सरकार की मजदूर किसान जनता विरोधी नीतियों को बेनका करते हुए आज गणतंत्र दिवस पर गोल चौराहा राऊ से महू शहर ड्रीमलैंड चौराहा से बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली तक अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर, आदिवासी एकता महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा वाहन जत्था निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में अनेक कार्यकर्ता वाहनों पर सवार थे कार्यकर्ता मोदी सरकार की किसानो वादा खिलाफी के विरोध में नारे लगा रहे थे। किसानों को एमएसपी की गारंटी देना होगी, लखीमपुर खीरी आंदोलन के किसनो के हथियारों को सजा दिलाने होगी, चार श्रम संहिताओं को निरस्त करो, 26000 प्रति माह न्यूनतम वेतन देना होगा, रेलवे प्रतिरक्षा बिजली आदि समेत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण नहीं किया जाए, रोजगारों का ठेका कारण करना बंद करो, रु. 600 मजदूरी प्रतिदिन देना होगी।

प्रतिवर्ष 200 दिन काम देकर मनरेगा को मजबूत करना होगा, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करो, 2013 के भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास कानून में पारदर्शिता तथा उचित मुआवज़े का अधिकार सुरक्षित करना होगा, लोकतंत्र तथा संघवाद की रक्षा करना होगी, बढ़ती सांप्रदायिकता पर शक्ति के साथ अंकुश लगाना होगा। कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर जन्मस्थली पर पहुंचकर जनतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किए जाने की शपथ के साथ वाहन जत्थे का समापन किया।

तत्पश्चा अंबेडकर जन्मस्थली पर सभा की गई जिसको संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड अरुण चौहान द्वारा आगामी फरवरी माह में संयुक्त किसान मोर्चे आव्हान के तहत आगामी 16 फरवरी को पहला संघर्ष कार्यक्रम होगा जब मजदूर, किसान, शोषित पीड़ित जनत के दूसरे तबको के साथ मिलकर रेल रोको रास्ता रोको और गांव बंद की अपनी कार्रवाइयों के जरिए देश भर में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सीधा संघर्ष करेंगे जुलूस और प्रदर्शनों का आयोजन करेंगे और केंद्र सरकार के संस्थानों के समक्ष धरने होंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील को दोहराते हुए आंदोलन के समर्थन को लेकर मजदूर संगठनो ने संयुक्त रूप से देश के छात्र नौजवान संगठन, सामाजिक संगठनों सहित साहित्यिक संगठनों से आंदोलन को अपना समर्थन देने की अपील की है सभा को किसान नेता श्री चौहान के अलावा राजू जरिया, काशीराम नायक, भादर भाई ने भी संबोधित किया।

आंदोलन में सुरेंद्र पटेल, सीताराम अहिरवार, शारदा बाई, ममता बाई भील, राकेश भील, रमेश चौहान, मनोहर भाई, अजय सिंग, राकेश नायक मुख्य नेतृत्व करी कार्यकर्ता के साथ अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

कामरेड अरुण चौहान
9770361010

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958